

उच्च शिक्षा और जनजातिय समुदाय की चुनौतियां एवं समस्याएं (खरगोन जिले के जनजाति समुदाय के सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर)

विनोद कुमार पटेल*

* शोधार्थी (समाजकार्य) रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां, अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, छात्रावासों में सीटों का आरक्षण तथा उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अन्य जातीय समुदाय की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं।

शब्द कुंजी – उच्च शिक्षा और जनजातिय समुदाय की चुनौतियां।

प्रस्तावना – अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा के विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 46 में विशेष प्रावधान दिये गये हैं। व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश या लिंगभेद किये बिना सर्वैधानिक समान अधिकार दिये गये हैं। यह राज्य सरकार को किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की प्रगति के लिये प्रावधान किये गये हैं। शिक्षा राज्य एवं केंद्र दोनों को ही अपने विषय क्षेत्रानुसार शिक्षा का प्रचार-प्रसार का दायित्व दिया गया है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं के समन्वयन के अनुरूप जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के साथ ही बालक-बालिकाओं के लिये छात्रावासों की स्थापना करना आदि है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग केंद्र भी खुलवाने का प्रावधान किया गया है। ये सब कार्यक्रमों के लिये कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों और केंद्रीय विद्यालयों के लिये साठे सात प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये विशेष बल दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां, अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, छात्रावासों में सीटों का आरक्षण तथा उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिये यह महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अन्य जातीय समुदाय की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं।

1991 की जनगणना के अनुसार 52.21 प्रतिशत सामान्य साक्षरता की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में 29.6 प्रतिशत ही साक्षरता पाई गई। इसे हम सारिणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो इस प्रकार से है-

सारिणी क्रं. - 1: अनुसूचित जनजाति समुदाय में साक्षरता अन्य वर्गों की तुलना में

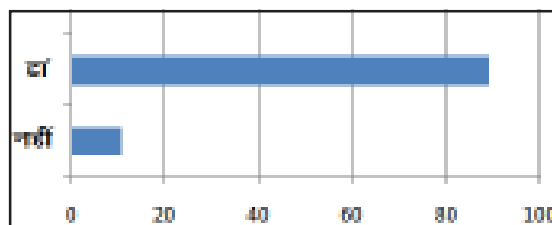
	कुल व्यक्ति प्रतिशत		पुरुष प्रतिशत		महिला प्रतिशत	
	1981	1991	1981	1991	1981	1991
सामान्य	36.23	52.21	46.89	64.13	24.82	39.29
अनु. जाति	21.38	37.41	31.12	49.91	10.93	23.76
अनु. जनजाति	16.35	29.60	24.52	40.65	8.04	18.19

उपरोक्त सारिणी से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति में साक्षरता की दर हमेशा से ही कम रही है। इसका मुख्य कारण अनुसूचित जनजातिय समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता, गरीबी, के अलावा शिक्षा की विषयवस्तु व पाठ्यक्रम समझ के बाहर होना, अपर्याप्त शैक्षणिक संस्थायें एवं सहायक सेवायें, शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षण का माध्यम व शिक्षा नीति ये सभी जिम्मेदार हैं।

सारिणी क्रं. - 2: उत्तरदाता को शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करने हेतु जानने से संबंधित वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	267	89 प्रतिशत
नहीं	33	11 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

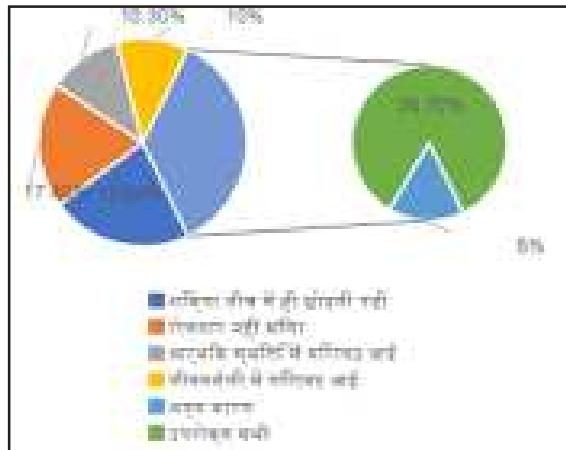
उत्तरदाता को शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करने हेतु जानने से संबंधित वर्गीकरण



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता को शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करने हेतु जानने से संबंधित वर्गीकरण करने पर प्राप्त हुआ कि 300 उत्तरदाताओं में से 267 लोगों का कहना है कि उनको धन के अभाव के कारण शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसका 89 प्रतिशत है, जो कि बहुत अधिक है जबकि 33 लोगों का कहना है कि उनको किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका 11 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों को शिक्षा संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सारिणी क्रं.- 3: उत्तरदाता से यदि हां तो उसका प्रभाव शिक्षा पर किस प्रकार पड़ा, जानने से संबंधित वर्गीकरण

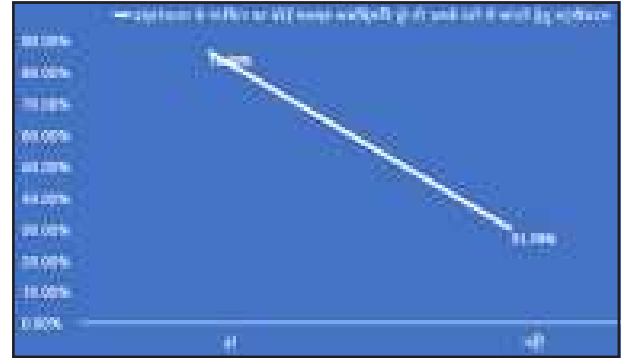
उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी	59	19.6 प्रतिशत
रोजगार नहीं मिला	52	17.4 प्रतिशत
आर्थिक स्थिति में गिरावट आई	31	10.3 प्रतिशत
जीवनशैली में गिरावट आई	30	10.0 प्रतिशत
अन्य कारण	15	5.0 प्रतिशत
उपरोक्त सभी	80	26.7 प्रतिशत
योग	267	89.0 प्रतिशत



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से यदि हां तो उसका प्रभाव शिक्षा पर किस प्रकार पड़ा, जानने से संबंधित वर्गीकरण करने पर प्राप्त हुआ कि 267 उत्तरदाताओं में से 59 लोगों का कहना है कि उन्हें शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी, जिसका 19.6 प्रतिशत है जबकि 52 लोगों का कहना है कि शिक्षा बीच में छूटने से उन्हें रोजगार नहीं मिला, जिसका 17.4 प्रतिशत है। उसी प्रकार 31 लोगों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, जिसका 10.3 प्रतिशत है जबकि 30 लोगों का कहना है कि उनकी जीवनशैली में गिरावट आई, जिसका 10 प्रतिशत है। 15 लोगों का कहना है कि अन्य कारण से समस्या उत्पन्न हुई जिसका 5 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है जबकि 80 लोगों का कहना है कि उन्हें उपरोक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसका 26.7 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों को धन के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सारिणी क्रं.-4: उत्तरदाता के परिवार का कोई सदस्य अशिक्षित हो तो उसके बारे में जानने हेतु वर्गीकरण

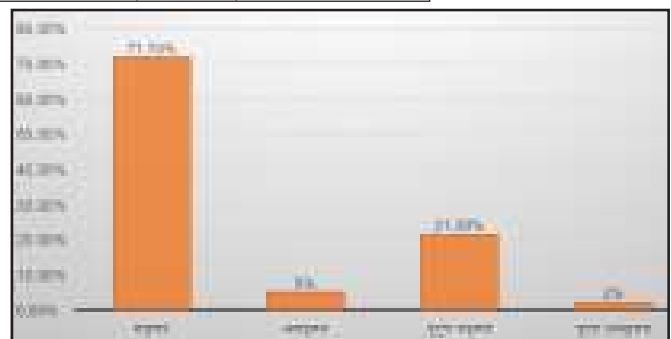
उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	235	78.3 प्रतिशत
नहीं	65	21.7 प्रतिशत
योग	300	100.0



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता के परिवार का कोई सदस्य अशिक्षित हो तो उसके बारे में जानने हेतु वर्गीकरण करने पर प्राप्त हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता के यहां कोई न कोई अशिक्षित है जिसकी संख्या 300 में से 235 एवं जिसका 78.3 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 65 लोगों के यहां कोई भी अशिक्षित नहीं है जिसका 21.7 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी गांवों में अशिक्षितों की संख्या अधिक है।

सारिणी क्रं.- 5: उत्तरदाता के दृष्टिकोण में अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व है या नहीं है, का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सहमत	215	71.7 प्रतिशत
असहमत	15	5.0 प्रतिशत
पूर्ण सहमत	64	21.3 प्रतिशत
पूर्ण असहमत	6	2.0 प्रतिशत
योग	300	100.0



उत्तरदाता का दृष्टिकोण जानने के लिये किये गये सर्वे के अनुसार 300 उत्तरदाताओं में से 215 लोग सहमत है कि अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व है जिसका 71.7 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 15 लोग असहमत है कि अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व है जिसका 5 प्रतिशत है। उसी प्रकार 64 लोग पूर्ण सहमत है जिसका 16 प्रतिशत है जबकि 6 लोग पूर्ण रूप से असहमत है जिसका 2 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर लोग अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व को समझते हैं।

सारिणी क्रं.-6: उत्तरदाता परिवार में शिक्षा ग्रहण करने के बारे में उनकी सोच जानने से संबंधित वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सभी को शिक्षा अनिवार्य है	156	52.0 प्रतिशत
शिक्षा से मानव विकास होता है	36	12.0 प्रतिशत
शिक्षा अनिवार्य नहीं है	9	3.0 प्रतिशत
शिक्षा अनिवार्य है लेकिन अधिक नहीं	17	5.7 प्रतिशत
शिक्षा रोजगार के लिये सहायक है	14	4.7 प्रतिशत
शिक्षा से जीवनशैली में बदलाव आता है	63	21.0 प्रतिशत
अन्य कारण	5	1.6 प्रतिशत
योग	300	100.0



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता परिवार में शिक्षा ग्रहण करने के बारे में उनकी सोच जानने से संबंधित वर्गीकरण करने पर ज्ञात हुआ कि 300 उत्तरदाताओं में से 156 उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है जिसका 52 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 36 लोगों का मानना है कि शिक्षा से मानव का विकास होता है जिसका 12 प्रतिशत है। उसी प्रकार 9 लोगों का मानना है कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है जिसका 3 प्रतिशत है जबकि 17 लोगों का मानना है कि शिक्षा अनिवार्य तो है लेकिन अधिक नहीं करनी चाहिये जिसका 5.7 प्रतिशत है। एवं 14 लोगों का मानना है कि शिक्षा रोजगार के लिये सहायक है जिसका 4.7 प्रतिशत है जबकि 63 लोगों का मानना है कि शिक्षा से जीवनशैली में बदलाव आता है जिसका

21 प्रतिशत है जबकि 5 लोगों का मानना है कि शिक्षा अन्य कारण से भी आवश्यक है जिसका 1.6 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है अधिकतर लोगों का मानना है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

1. खरगोन जिले के अधिकांश लोगों को शिक्षा संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
2. अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है।
3. सर्वेक्षित परिवारों का मानना है कि शिक्षा अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिये अनिवार्य है।
4. जिले के अधिकांश लोगों को धन के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
5. वर्तमान में खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अशिक्षितों की संख्या अधिक है।
6. अशिक्षित होने पर रोजगार न मिलना, उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आना के साथ ही उनकी जीवनशैली में भी गिरावट आ गई। इस प्रकार उन्हें अनेकों प्रकार की चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाजन, डॉ. संजीव, (2011), '**आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन**', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
2. मिश्र, उमाशंकर एवं तिवारी, प्रभात कुमार, (1975), '**भारतीय आदिवासी**', उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ
3. मुराब, श्रीमती इन्दु, (1994-95), '**भिलाला जनजाति का संक्षिप्त मानवशास्त्रीय अध्ययन**', आदिम जाति अनुसंधान, भोपाल, मध्यप्रदेश
4. मेहता महेश कुमार, (1976), '**मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति**', रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
5. नदीम हसनैन (2000), '**जनजातीय भारत**' जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली पृ. 12
6. प्रसाद डा. दिवाकर (2020), '**आधुनिक भारत में आदिवासी जीवन एवं संघर्ष**', जे.टी. एस. पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 177
